IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

नई शिक्षा नीति 2020 का स्वरुप और चुनौतियाँ

Dr. Rajesh Kumar
Assistant Professor
Ganpati Institute of Science & Technology, Mohan Nagar, Ghaziabad, UP, India
rajeshrajora2017@gmail.com

सरांशः

जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा के बिना कुछ भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। शिक्षा के माध्यम से हम सभी अपने सपने साकार कर सकते है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति, समाज और देश का विकास होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति अपनाई गई। भारत देश की शिक्षा प्रणाली में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति 29 जुलाई, 2020 को लागू की गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 तथा 1986 में भी शिक्षा नीतियाँ लागू की गई थी।नई शिक्षा नीति 2020 के लागू करने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर **शिक्षा मंत्रालय** कर दिया गया है। अर्थात् इस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब मानव संसाधन विकासमंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जायेगा। नई शिक्षा नीति के तहत सकल घरेलु उत्पादन (GDP) का 6 प्रतिशत खर्च इसमें किया जायेगा जो पहले 4.43 फीसदी ही था।

जैसे की कोई वस्तु एक जगह पर पड़ी रहती है तो उस पर धुल जम जाती है। पहले की शिक्षा नीति का भी यही हाल था। पुरानी शिक्षा नीति में शिक्षाकी उन्नति और प्रगति कही न कही रुक सी गई थी। इसलिए शिक्षा नीति में भी परिवर्तन लाया गया। इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया जब नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से बाल केन्द्रित बनाया गया।इसमें मातृभाषा, स्थानीय भाषा पर जोर दिया जायेगा। विषयों का चयन दिनचर्या पर छोड़ दिया जाएगा और 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। नई शिक्षा नीति से हम सशक्त नव भारत निर्माण की आशा करते है। बस आवश्यकता है उसे प्रभावी तरीके से लागू करने की। अगर सच में उसका क्रियान्वयन हुआ तो भारत की युवा पीढी ज्ञान–विज्ञान के रास्तों को खोलकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगी।

मुख्य शब्दः नई शिक्षा नीति,शिक्षा मंत्रालय,मातृभाषा,स्थानीय भाषा,क्रियान्वयन,ज्ञान–विज्ञान।

शिक्षा नीति का इतिहासः

देश में एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। भारत में अब तक तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां लागू की जा चुकी हैं। ये तीन नीतियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था।नई शिक्षा नीति पिछली शिक्षा नीति की कमियों और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखतेहुए लाई गई है, जिससे स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी सुधार हो सकते हैं। जून, 2017 में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा मई, 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गयाथा।

शिक्षा नीति का परिचयः

पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरी दुनिया तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 29 जलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया। यह शिक्षा नीति 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यः

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। नई शिक्षा नीति 2020 में कुछ बदलावों का प्रस्ताव है,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय उच्च शिक्षा का उद्घाटन, कई विकास विकल्पों के साथ चार वर्षीय बहु–विषयक स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत शामिल है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।एनईपी 2020 नीति में यह भी प्रस्तावित है कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का लक्ष्य 2040 तक बहु–विषयक होना है। यह नीति देश में रोजगार को बढ़ावा देगी और हमारी शिक्षा प्रणाली को मौलिक रूप से बदल देगी।

नई शिक्षा नीति के सिद्धांतः

लचीलापनः

यहनीतिशिक्षार्थियों को अपनी सीखने की गति चुनने और अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना रास्ता चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करना चाहती है।

बहु–विषयकः

विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कोडिंग, कला, मानविकी, खेल आदि सभी क्षेत्रों में समग्र शिक्षा प्रदान करना।

नैतिक और संवैधानिक मूल्यः

इसका उद्देश्य सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, समानता और न्याय के मूल्यों को विकसित करना है।

सतत् नीतिः

भारत की समृद्ध विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली और परंपरा को ध्यान में रखते हुए, जमीनी हकीकत के नियमित मूल्यांकन के आधार पर नीतियां बनाना।

समानता और समावेशः

सभी शैक्षिक निर्णयों का उद्देश्य होगा, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ सकें।

जीवन कौशलः

जीवन कौशल जैसे सहयोग, टीम वर्क, संचार, लचीलापन, आदि के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।

व्यावसायिक मूल्यः

सभी शिक्षकों को कड़ी तैयारी के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। तैयारी, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा विकास पर जोर दिया जाएगा।

मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षाः

शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है न कि व्यावसायिक गतिविधि। यह सभी के लिए पर्याप्त गुणवत्ता के साथ उपलब्ध होनी चाहिए। एक जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के साथ–साथ एक नैतिक और परोपकारी निजी प्रणाली में मजबूत और स्थायी निवेश होना चाहिए।

नई शिक्षा नीति 2020 का स्वरुपः

यह नीति मौजूदा 10+2स्कूल प्रणाली को 5+3+3+4की एक नई प्रणाली में पुनर्गठित करने की बात करती है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पाठ्यक्रम और शिक्षण का आधार है। वर्तमान में, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को 10+2संरचना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है।वर्तमान 10+2प्रणाली को क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 वर्ष की आयु के अनुसार एक नई 5+3+3+4पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

फाउंडेशन स्तर 5 वर्षः

फाउंडेशन स्तर 5 वर्षको दो भागों में बांटा गया है। आंगनबाडी में पहले तीन साल तक बच्चे प्री–स्कूली शिक्षा लेंगे। इसके बाद अगले दो साल तक बच्चे एक स्कूल में कक्षा 1 और 2 में पढ़ेंगे। इन 5 वर्षों के अध्ययन के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसमें 3 से 8 साल के बच्चे शामिल होंगे।

प्रारंभिक स्तर 3 वर्षः

प्रारंभिक चरण 3 वर्षमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस दौरान बच्चों को प्रयोग के माध्यम से विज्ञान, गणित, कला आदि की शिक्षा दी जाएगी। इस चरण में 8 से 11 साल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा।

माध्यमिक स्तर 3 वर्षः

इस चरण में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढाए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स भी कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे, जिसमें बच्चों को तरह–तरह के हुनर सिखाए जाएंगे। कक्षा 6 से ही बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी कक्षा 6 से शुरू होगी। इस चरण में 11 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा।

उच्चमाध्यमिक स्तर 4 वर्षः

इस चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र दो चरणों में पढ़ाई करेंगे। पहले चरण में कक्षा 9 और 10 के छात्र और दूसरे चरण में कक्षा 11 और 12 के छात्र होंगे।

छात्रों को विषय चुनने की भी छूट होगी। कुछ विषय ऐसे होंगे जो सभी के लिए सामान्य होंगे और कुछ वैकल्पिक विषय होंगे जैसे–कला, संगीत, व्यावसायिक विषय आदि। जिनमें से छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन कर सकेंगे। इस चरण में 14 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 में मुख्य रुप से शिक्षण माध्यम के रुप में भाषा के सवाल को मुख्य रूप से उठाया गया है। जिसके लिए एक अध्याय **'बहु–भाषावाद और भाषा की शक्ति'** शीर्षक रखा गया है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा की शक्ति को पहचानते हुए विभिन्न प्रावधान व सुझाव इस शिक्षा नीति में किये गये है। इसमें कहा गया है कि ''छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते है और समझ लेते है।''

देश की उन्नति में बिना मातृभाषा के ज्ञान और अध्ययन के सब व्यवहार व्यर्थ है। मातृभाषा से बच्चों का परिचय घर और परिवेश से ही शुरू हो जाता है। इस भाषा में बातचीत करने और चीजों को समझने–समझाने में आसानी होती है। अगरउनकी इस क्षमता का इस्तेमाल पढाई के माध्यम के रुप में मातृभाषा का चुनाव करके किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते है।

नई शिक्षा नीति की विशेषताएं:

1) नई शिक्षा नीति 2020 आजादी के बाद की तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है जिसमें बुनियादी तौर परपरिवर्तन किये गये हैं।
2) इस शिक्षा नीति में शिक्षा क्षेत्र को तकनीकी से जोड़ा जाएगा,सभी स्कूलों में डिजिटल संसाधन मुहैयाकराने का प्रावधान है।
3) प्रस्तुत शिक्षा नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को क्षेत्रीय भाषा में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिल सकेगा।
4) नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब शिक्षा में कई प्रकार के विकल्प बच्चों को दिए जाएंगे। अब दसवीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा जिसमें छात्र कोई स्ट्रिम ना चुनकर अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुन सकेगा।
5) नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को छठीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी।
6) साथ ही साथ शैक्षिक क्षेत्रों में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुणवत्ता को उच्च किया जा सके।
7) नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही 10+2के शैक्षिक पॅटर्न को बदलकर 5+3+3+4के नए शैक्षिक पॅटर्न को चुना गया है। जिसमें तीन साल की फ्री स्कूली शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी।
8) नई शिक्षा नीति के भीतर शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा।इसमें कुछ शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जैसे– मेडिकल और लॉ।
9) ''1986 की शिक्षा नीति के तहत अबतक उच्च शिक्षा में कई नियामक कार्य कर रहे थे। जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय वास्तुकला परिषद्, भारतीय फार्मेसी परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

आदि। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में विधि और चिकित्सा शिक्षा को छोडकर बाकी सारी उच्च शिक्षा को एक ही नियामक के अंदर लाने का निर्णय किया गया है।''

नई शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ:

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 34 वर्षो बाद शैक्षिक ढांचे को बेहतर बनाने का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय कदम है।लेकिन जिस प्रकार किसी योजना के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलु होते है, उसी प्रकार नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में सरकार के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों को निम्न रूप में देखा जा सकता है –

1) इन चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि वर्तमान में हमारे देश के अंदर एक तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। नई शिक्षा नीति में इस पर गंभीरतासे चिंतन होना आवश्यक है। इसमें भी चिंता इस बात की है की बीच में ही स्कूल छोडनेवाले अधिकांश बच्चे अनसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, आदिवासी और दिव्यांग समुदाय के है।

2) दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है स्कूल, कॉलेजों की संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है। लेकिन उन्हे बिजली, पानी, शौचालय, चारदीवारी, पुस्तकालय, कंप्यूटर आदि संसाधन मुहैया कराने में सरकार असमर्थ रही है।

3) नई शिक्षा नीति में तीसरी और महत्वपूर्ण चुनौती है देश भर के नगरों से लेकर कस्बों तक में अध्यापकों की कमी को दूर करना। अध्यपकों की कमी का सीधा असर गुणवत्ता पर होता है।

4) साथ ही साथ चौथी चुनौती है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता देना।

5) पांचवीं चुनौती है पाचवीं कक्षा तक स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाना उतना आसान कार्य नहीं लग रहा है। जैसे अगर कोई बच्चा गुजरात में रहकर गुजराती भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है और यदि वह छात्र किसी कारणवश पंजाब में चला जाता है तो उसे भाषा चयन को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वह किस भाषा में पढाई करेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह है।

6) साथ ही देश के अंतर्गत सरकारी स्कूलों का स्तर चिंताजनक है। इस पर भी नई शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान दिखाई नहीं देता।

7) नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर 6 फीसदी जीडीपी खर्च करने की योजना है, लेकिन प्रथम शिक्षा नीति 1968 से लेकर सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी वही लक्ष्य रखा गया था। लेकिन यह संभव नहीं हो सका। 2017–18 के सर्वे के अनुसार जीडीपी का केवल 2.7 फीसदी ही शिक्षा पर खर्च किया गया है। अब नई शिक्षा नीति में सरकार के सामने चुनौती है की वर्तमान जीडीपी 2.7 से 6 फीसदी तक ले जाने में कैसे सफल हो पायेगी? इस संदर्भ में सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है।

8) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से शिक्षा व्यवस्था महंगी होने की उम्मीद है।

9) वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा में कुशल शिक्षकों की कमी है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक दिक्कतें देखने को मिल रही हैं।

10) विदेशी विश्वविद्यालयोंके प्रवेश से कुशल भारतीय शिक्षकों का पलायन करना।

11) शिक्षक–शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफटीई), एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

निष्कर्ष:

शिक्षा किसी भी समाज और देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक आवश्यक और अपरिहार्य तत्व है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक राष्ट्र द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति में शिक्षा सुधारों की नई उम्मीदों के साथ–साथ कुछ चुनौतियाँ भी है। लेकिन किसी भी योजना के मायने तब सबित होते हैं जब हमउसे जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने में कितने सफल हो पाते। सशक्त भारत के निर्माण के लिए शिक्षा का ढांचा सुधारना आवश्यक है। हम आशा करते है कि बदलते शिक्षा परिदृश्य में 21वीं सदी के अनुसार इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं जो शिक्षा के वर्तमान स्तर को सुधारने में अवश्य मददगार साबित होंगे। नई शिक्षा नीति से हम सशक्त नव भारत निर्माण की आशा रखते है। आवश्यकता है उसे प्रभावी तरीके से लागू करने की। अगर सच में उसका क्रियान्वयन हुआ तो भारत की युवा पीढी ज्ञान–विज्ञान के रास्तों को खोलकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगी, इसमें संदेह नहीं है। इस नई शिक्षा नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कैसे लागू किया जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत सबसे कम उम्र की आबादी वाला देश है और भारत का भविष्य इन युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर निर्भर करेगा।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

संदर्भ सूची

[1]. Hindi.nysha.org
[2]. नई शिक्षा नीति और हिंदी–नवज्योति, नई दिल्ली।
[3]. Tv9hindi.com
[4]. भावना मासीवाल का लेख–Tv9 14 सितंबर, 2021
[5]. हिंदी साहित्य : युग और प्रवृतियाँ–डॉ. शिवकुमार शर्मा
[6]. शिक्षा नीति से जुडी चुनौतियाँ– डॉ. वारिंदर भाटिया (दिव्य हिमाचल.कॉम)
[7]. https://www.education.gov.in.PDF
[8]. National Education Policy 2020
[9]. रिपोर्ट 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
[10]. दा टाईम ऑफ इंडिया,05/09/2020
[11]. नई शिक्षा नीति 2020 फक्टस जुलाई 30, 2020
[12]. टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट, 2015
[13]. https://en Wikipedia.org
[14]. यशपाल समिति रिपोर्ट, 1992